

प्रेषक,

श्री. शंकर अग्रवाल,  
सचिव, वित्त व्यवस्थापन,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण/सिंचाई विभाग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,  
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

अनुभाग-2:

लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 1977

विषय:- प्रतिशत प्रभार की दर ।

सहोदय,

मुझे आपसे यह ज्ञान का निदेश हुआ है कि वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-3220/दस-1744/75, दिनांक 1 अक्टूबर 1975 एवं शासनादेश संख्या-ए-2-2201/दस-1744/75, दिनांक 13 जुलाई 1976 के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों और वाणिज्यिक विभागों के कार्य के लिये, कार्य की लागत का 15 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज चार्ज) निर्धारित हैं। सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों में भी उनके द्वारा डिपॉजिट के रूप में किये जा रहे राजकीय कार्यों पर प्रतिशत प्रभार कार्य की कुल लागत में 5 प्रतिशत कमी करने के खात उपलब्ध लागत का 15 प्रतिशत अनुमन्य किया जाता है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त कार्या के सम्बन्धित विभाग से सम्बन्धित डिपॉजिट के रूप में किये जाने वाले कार्यों पर प्रतिशत प्रभार नहीं लिया जाता है।

2- शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि प्रतिशत प्रभार अब कार्य की लागत का 12.5 प्रतिशत की दर से वसूल किया जाय एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा डिपॉजिट के रूप में किये जा रहे सम्बन्धित राजकीय कार्यों पर इसी दर से प्रतिशत प्रभार वसूल किया जाय। इस प्रतिशत प्रभार में 1 प्रतिशत आडिट एवं रकाउन्ट प्रुक्क सम्बन्धित हैं, तथा इतका विभाजन आवश्यकतानुसार निम्नलिखित रूप से होगा:-

पूर्ण परियोजनाएं एवं व्यौटोकर अनुमान  
धारात्मिक अनुमानों के व्यय तहिया  
अधिष्ठान की मद में डाला जाएगा ।

1.5 प्रतिशत

कार्यों का निष्पन्न लेखा परिक्षा ... 1. प्रतिशत सहित

जिन मामलों में देका प्रासांगिक परियोजनाएं और अनुसंधान प्राकल्पन बनाई जाएंगे आधिकारिक की मद में डाला जाएगा।

3- सार्वजनिक उपकरणों एवं निगमों एवं अन्य निर्माण इकाइयों/विभागों द्वारा शासकीय संस्थाओं द्वारा शासकीय कार्य विभाजित के रूप में किये जाने पर केन्द्रीय उन्हीं पूर्व की प्रकृति का लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत अनुसन्ध होना।

4- ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। इसे आगमन जिनकी विस्तृत स्वीकृति निर्मित की जा चुकी है, पुराने अध्यायित : 2000 : नहीं होंगे परन्तु: यदि पुराने अध्यायित आगमन जिनमें लागत में वृद्धि की गयी है, पुनः स्वीकृति हेतु शासन/व्यय अधिकारियों की सलाहदेश के तन्मन की तिथि के बाद प्राप्त होते हैं तो उन पर वही लागत की धराशि पर प्रतिशत लागत इस आदेशादेश में उल्लिखित पर पर अनुसन्ध होगी। वित्तीय विभाग एवं आवश्यक संशोधन व्यवस्था, किये जायेंगे।

5- लागत का अंश में अनुसन्ध विवेकीय आगमन अध्यायित संशोधित अधिकाधिक को अतिरिक्त प्रदर्शित करने का हक नहीं।

अनुवीय,

[ शेखर अग्रवाल ]  
सचिव  
वित्त, व्यय, नियंत्रण।

पुणे-2-07-81/क-77-त-विभाग

आदेशादेश निम्नलिखित सूचनाओं एवं अनुसन्ध का प्रकाश देते हैं।

- 1- ...
- 2- ...
- 3- ...
- 4- ...
- 5- ...
- 6- ...
- 7- ...
- 8- ...
- 9- ...

...

01  
दिनांक 15/11/04  
73  
14/11/04

संख्या-3058/नौ-5-2004-145सा/2004

प्रेषक,  
मोहिन्दर सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
प्रबन्ध निदेशक,  
उ०प्र० जल निगम,  
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक: 22 दिसम्बर, 2004

विषय:- प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज) चार्ज की दर।

महोदय,

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ०प्र० जल निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज) चार्ज अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है:

- (1) केन्द्रीय योजनाओं में से गंगा कार्यकारी योजनाओं पर भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार 08 प्रतिशत सेन्टेज अनुमन्य है। उक्त योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा 4.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार अनुमन्य किया जाता है। इस प्रकार कुल 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार अनुमन्य होगा।
  - (2) त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना हेतु वर्कचार्ज अधिष्ठान के लिये 5.0 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, के स्थान पर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- ए-2-87/दस-97-17(4)/75, दिनांक 27.02.1997 के अनुसार उक्त योजनाओं पर 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार अनुमन्य होगा।
  - (3) त्वरित नागर पेयजल कार्यक्रम हेतु 3.0 प्रतिशत वर्कचार्ज तथा 5.0 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, इस प्रकार कुल 08 प्रतिशत प्रभार के स्थान पर वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1118/दस-99-17(4)/75, दिनांक 24.03.1999 के अनुसार उक्त योजनाओं पर 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार वसूल किया जायेगा।
  - (4) शासनादेश संख्या-ए-2-1118/दस-99-17(4)/75, दिनांक 24.3.1999 के अनुसार पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि एवं विधायक निधि पोषित योजनाओं से संबंधित डिपाजिट कार्य पर सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य निर्माण इकाइयों/स्वायत्त शासी संस्थाओं को उक्त 12.5 प्रतिशत की दर से अनुमन्य सेन्टेज चार्ज उक्त योजनाओं से संबंधित डिपाजिट कार्य पर उ०प्र० जल निगम को भी अनुमन्य कराया गया है।
- 2- यह आदेश दिनांक: 01.04.2004 से प्रभावी होंगे। उक्त निर्णय (ऑन गोइंग) योजनाओं पर भी प्रभावी होगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-1422/दस-04, दिनांक 20.12.2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
ह0/-  
(मोहिन्दर सिंह)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
  - 2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
  - 3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
  - 4- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - 5- सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0शासन।
  - 6- सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
  - 7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
  - 8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
  - 9- वित्त लेखा अनुभाग-2/वित्त (व्यय)नियंत्रण अनुभाग-8।
  - 10- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
  - 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
ह0/-  
(मोहिन्दर सिंह)  
प्रमुख सचिव

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक:

11/पी-1/ वित्तीय प्रबन्धन /01

दिनांक: 12/01/2005

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-1/2), उत्तर प्रदेश जल निगम।
  - 2- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम।
  - 3- समस्त अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम।

(ए0के0 श्रीवास्तव)  
सचिव(व्यवस्था)